

कृषि विभाग

दिनांक 20 मार्च, 2014

क्रमांक 2005-कृषि-II(4)2014/4624.—उर्वरक पोषक तत्वों, जैव उर्वरकों तथा जैविक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उर्वरकों के अतिरिक्त प्रयोग को रोकने के लिए इन विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु राज्य सरकार का एक मंच प्रदान करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल एक राज्य स्तरीय उर्वरक परामर्श समिति का गठन करते हैं। उर्वरक परामर्श समिति का गठन निम्न को शामिल करके किया जाएगा।

(i)	कृषि मंत्री, हरियाणा	अध्यक्ष
(ii)	कृषि राज्य मंत्री, हरियाणा	उप-अध्यक्ष
(iii)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
(iv)	कृषि निदेशक/कृषि महानिदेशक हरियाणा	सदस्य
(v)	प्रबंधक निदेशक हैफेड	सदस्य
(vi)	राज्य प्रबंधक, इफको, कृमको, एनएफएल एवं आईपीएल	सदस्य
(vii)	संयुक्त निदेशक कृषि (उर्वरक)	सदस्य सचिव
(viii)	तीन प्रगतिशील किसान (जिसमें एक महिला किसान सम्मिलित है)	सदस्य
(ix)	तीन उर्वरक विक्रेता	सदस्य

2. यह समिति निम्न में दिए गये मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा तथा सुझाव एवं सिफारिश देगी।

- किसानों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से उर्वरक पोषक तत्वों, जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने बारे।
- उर्वरकों की कमी यदि कोई है तो तब राज्य में उर्वरकों का सही व एक समान वितरण को सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना।
- किसानों के लिए उर्वरकों को पहुंच में लाना।
- उर्वरकों की दुलाई में सुधार करके किसानों की अधिकतम पहुंच में लाना एवं कम लागत करने बारे।
- उर्वरकों के कृषि के अतिरिक्त अन्य गैर-कृषि प्रयोग को रोकने बारे।
- पोषक तत्वों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरकों को अनुकूलित करना।
- स्थिर कृषि के उद्देश्य से कोई अन्य मुद्दा।

3. सरकारी सदस्यों के टी०ए०डी०ए० का भुगतान उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के टी०ए०डी०ए० का भुगतान कृषि विभाग से 2401-फसल उत्पादन 105-मैन्योर एवं फर्टीलाइजर (योजना स्कीम)-एस०बी०-96 कृषि आदानों का गुणवत्ता नियंत्रण स्कीम के तहत किया जाएगा।

5. गुणवत्ता मुद्दों में से किसी के आने पर उर्वरक परामर्श समिति की बैठकों के रूप में बैठक आयोजित की जाएगी।

रोशन लाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 20th March, 2014

No.2005-Agri.II(4)/2014/4624.— The Governor of Haryana is pleased to constitute the State Level “Fertilizer Advisory Committee” to provide a platform to the State Government for deliberating on issues such as promotion of balance application of fertilizer nutrients, bio fertilizers and organic fertilizers, to ensure adequate and timely availability of fertilizers to the farmers and to check their diversion, with the objective of realizing the maximum benefit to the farmers. The constituted “Fertilizer Advisory Committee” would be as under :—

(i)	Agriculture Minister, Haryana	Chairman
(ii)	Minister of State for Agriculture, Haryana	Vice Chairman
(iii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government Haryana, Agriculture Department	Member
(iv)	Director Agriculture/Director General Agriculture, Haryana	Member
(v)	Managing Director, HAFED	Member
(vi)	State Manager, IFFCO, KHRIBCO, NFL and IPL	Members
(vii)	Joint Director Agriculture (dealing with fertilizers)	Member-Secretary
(viii)	Three progressive farmers (including one women farmer)	Members
(ix)	Three dealers (fertilizer)	Members

2. The Committee shall deliberate and suggest/recommend measures on issues such as:

- (i) Promotion of balanced application of fertilizer nutrients, bio-fertilizers and organic fertilizers with the objective of realization of optimal benefits to the farmers.
- (ii) Shortage of fertilizers, if any, in the State to ensure equitable distribution of fertilizers.
- (iii) Quality of fertilizers and to suggest ways to ensure supply of quality fertilizers.
- (iv) Affordability of fertilizers for the farmers.
- (v) Improvement in the transportation of fertilizer to maximize the reach and to minimize the cost.
- (vi) Illegal diversion of fertilizers to any no-agricultural use.
- (vii) New customized fertilizer for increasing the efficacy of nutrients.
- (viii) Any other issue in the interest of sustainable agriculture.

3. T A/DA of official members shall be borne by their respective departments.

4. TA/DA of official non-official members shall be borne by the Agriculture Department from the Head 2401-Crop Husbandry-105-manures & Fertilizer (Plan Scheme)-SB-96 Scheme for Quality control of Agriculture Inputs.

5. The meetings of the “Fertilizer Advisory Committee” would be organized as and when any of the above-stated issues come up.

ROSHAN LAL,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.